

शिक्षा मंत्री की स्वीच्छिक निधि से वित्तीय सहायता ?

747. श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्यार्थियों (लड़कों और लड़कियों) के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1968 में शिक्षा मंत्री स्वीच्छिक निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है, और

(ख) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के ऐसे विद्यार्थियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1968 से वित्तीय सहायता दी जा रही है और उनमें से प्रत्येक विद्यार्थियों का कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) और (ख) . दो विवरण, जिनमें अपेक्षित सूचना दी गयी है, भ्रमा पटल पर रख दिये गये हैं। (ग्रन्थानुसूचक संख्या LI-246 171)

पब्लिक स्कूल

748. श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अप्रैल, 1971 को भाषण देते हुए केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि देश में सभी पब्लिक स्कूल बन्द कर दिये जाने चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी पब्लिक स्कूलों तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा रखने का है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. पी. यादव) : (क) और (ख) . विवरण संलग्न है।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) शायद माननीय सदस्य का आशय रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए भाषण के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से है। तथापि प्रैम रिपोर्टें पूर्णतया ठीक नहीं हैं। रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि पब्लिक स्कूलों को या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए या इन्हें योग्यता के आधार पर सभी के लिए खोल दिया जाए। शिक्षा में वर्ग पद्धति नहीं होनी चाहिए।

(ख) पब्लिक स्कूलों सहित सभी विधेय स्कूलों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में किया गया है, अर्थात् पब्लिक स्कूलों सहित सभी विधेय स्कूलों में छात्रों का दायित्व योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और सामाजिक वर्गों के पृथक्करण को बचाने के लिए पूरी फीस माफी का अनुपात विहित कर देना चाहिए। परन्तु इससे